



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1940 (श०)

(सं० पटना ५२९) पटना, वृहस्पतिवार ७ जून २०१८

सं० ०८ / नि०था०-११-२०/२०१४सा०प्र०-३८०२
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 मार्च 2018

श्री राजमंगल राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-५०४/११ को जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण व्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक 14.09.2006 को परिवारी श्री हरेन्द्र सिंह से 20,000/- (बीस हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं उनके विरुद्ध निगरानी थाना कोड सं०-०५२/२००६ दिनांक 13.09.2006 दर्ज होने की सूचना जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-२२६१/गो० दिनांक 17.09.2006 द्वारा प्राप्त हुई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-११४३३ दिनांक 11.11.2006 द्वारा श्री राम को हिरासत की तिथि (दिनांक 14.09.2006) के प्रभाव से निलंबित किया गया। उक्त कृत्य में निहित आरोपों के लिए श्री राम के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री राम का स्पष्टीकरण (दिनांक 03.05.2008) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपना बचाव प्रस्तुत किया। सम्यक् विचारोपांत मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-२००५ के नियम-१७(२) के आलोक में संकल्प ज्ञापांक-६६३९ दिनांक 10.07.2009 द्वारा श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों पर श्री राम से बचाव बयान प्राप्त किया गया। इसके उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड विनिश्चित किया गया तथा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में आयोग द्वारा अपनी सहमति संसूचित की गयी। तत्पश्चात् राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-९०७२ दिनांक 24.07.2017 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरहीता होगी) का दंड संसूचित किया गया।

२. श्री राम ने उक्त दंडादेश के विरुद्ध अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन, दिनांक 05.09.2017 समर्पित किया। अपने अभ्यावेदन में उन्होंने निगरानी द्वारा की गयी कार्रवाई को अनुचित बताते हुए यह तर्क दिया है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पदस्थापन काल में उन्होंने ट्रक सं० UP 78 N 2699 को ओवर लोडिंग एवं संदिग्ध कागजात होने के आधार पर अर्थ दंड लगाया था। निगरानी द्वारा जुर्माना की राशि वसूले जाने से संबंधित इस मामले को जबरन रिश्वत लेने का मामला बनाया गया तथा संचालन पदाधिकारी ने भी सम्भावनायों के आधार पर अपना निष्कर्ष प्रतिवेदित किया। अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में

निर्धारित समय—सीमा का अनुपालन नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सदर्भित ट्रक के कागजात के कालातीत होने का तथ्य उजागर करते हुए स्वयं द्वारा की गयी कार्रवाई को न्यायोचित ठहराया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिये जाने एवं द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में निहित तथ्यों का संज्ञान नहीं लिये जाने का भी मामला उठाया है।

3.विषयगत आरोप से संबंधित उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संचालन पदाधिकारी ने आरोपी पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी को सुनते हुए विश्लेषणात्मक स्थिति के साथ अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। इस क्रम में श्री राम से प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक 23.02.2017) में निहित तथ्यों की गहन समीक्षा की गयी तथा यह पाया गया कि तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में श्री राम ने ट्रक सं०- UP 78 N-2699 के संदर्भ में वाहन मुक्ति आदेश बुक में प्रविष्टि के पूर्व जुर्माना की राशि का रसीद निर्गत करने संबंधी कार्रवाई नहीं की गयी। जिससे रिश्वत माँगने एवं लेने की घटना/औचित्य की पुष्टि होती है। इसके साथ ही गिरफ्तार किये जाने के बाद रूपये की बारामदगी एवं उनके हाथ में लगे रसायन के धोवन की पुष्टि गवाहों द्वारा किये जाने से भी उनके रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित हुआ है। इस संबंध में श्री राम द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

वस्तुतः श्री राम को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम—(3) एवं नियम—(14) के प्रावधानों के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में अपने विहित दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था। परन्तु उनके द्वारा नियमानुकूल कार्य नहीं किया गया एवं जब्त ट्रक को मुक्त करने हेतु रिश्वत ली गयी जो विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित हुआ। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण व्यूरो के पत्रांक—2290 दिनांक 12.12.2014 द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०-52/2006 दिनांक 13.09.2006 में एतदसंबंधी आरोप सत्य पाये गये एवं इसके आलोक में विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में आरोप पत्र सं०-72/2006 दिनांक 11.11.2006 समर्पित हुआ। विधि विभाग के आदेश सं०-4201 दिनांक 11.11.2006 द्वारा उक्त कांड में अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत हुआ। श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9072 दिनांक 24.07.2017 द्वारा 'सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरहता होगी)' का दंड संसूचित किया गया।

4.उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री राम ने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 05.09.2017) समर्पित किया। सम्यक विचारोपरांत श्री राम के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16525 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दण्ड को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।

5.विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9072 दिनांक 24.07.2017 की कंडिका 07 के अनुपालन में श्री राम के निलंबन अवधि (दिनांक 14.09.2006 से दिनांक 24.07.2017) के वेतन भुगतान हेतु विभागीय पत्रांक 12026 दिनांक 18.09.2017 द्वारा कारण—पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री राम का कारण पृच्छा/स्पष्टीकरण (दिनांक 12.11.2017) प्राप्त हुआ।

आरोप, जाँच प्रतिवेदन, दंडादेश एवं श्री राम से प्राप्त कारण पृच्छा/स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा के आधार पर निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य नहीं पाया गया।

6.अतएव सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9072 दिनांक 24.07.2017 द्वारा पारित दंडादेश के क्रम में श्री राजमंगल राम, बिप्र०से०(सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निम्नवत आदेश पारित किया जाता है :—

"निलंबन अवधि (दिनांक 14.09.2006 से दिनांक 24.07.2017 तक) के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।"

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम विशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 529-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>